लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *495
26 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग में कौशल विकास

***495. डॉ. निशिकांत दुबेः**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए इस समय कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) झारखंड और अन्य राज्यों में कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए विगत दो वर्षों के दौरान विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) इत्यादि को आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>दिनांक 26.07.2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *495 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।</u>

(क): वस्त्र क्षेत्र की कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए मंत्रालय वर्ष 2010-2011 से 2017-18 तक एकीकृत कौशल विकास योजना एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत 11.14 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें से 8.43 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। कुल प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों में से 7.94 लाख महिलाएं, 2.32 लाख अनुसूचित जाति, 0.77 लाख अनुसूचित जनजाति और 3176 व्यक्ति दिव्यांग थे।

वस्त्र उद्योग में कौशल की कमी को पूरा करने के मंत्रालय के प्रयास को जारी रखने के लिए 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2019-20 तक की 3 वर्ष की अवधि के लिए समग्र मूल्य श्रृंखला (संगठित क्षेत्र में स्पिनिंग और विविंग को छोड़कर) में विभिन्न कार्य की भूमिकाओं में लगभग 10 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ 'समर्थ' नामक एक नई योजना शुरू की गई है। क्रियान्वयन का समग्र ढ़ांचा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा अपनाए गए कौशल विकास के विस्तृत नीतिगत ढ़ांचा अर्थात् सामान्य मानदंड, राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढ़ांचा (एनएसक्यूएफ) आदि के अनुरूप है। एमएसडीई के सामान्य मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण भागीदार को योजनागत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

हथकरघा क्षेत्र : हथकरघा बुनकरों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बुनकर सेवा केन्द्रों (डब्ल्यूएससी) के माध्यम से झारखण्ड राज्य सहित देशभर में विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)/व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) में किया जाता है।

हस्तशिल्प क्षेत्र : हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय मानव संसाधन विकास योजना क्रियान्वित कर रहा है ताकि हस्तशिल्प क्षेत्र को योग्यता प्राप्त और प्रशिक्षित कार्यबल मुहैया कराया जा सके और डिजाइनरों के प्रशिक्षित कैडर के रूप में इस क्षेत्र के लिए मानव पूंजी का भी सृजन किया जा सके।

रेशम उत्पादन क्षेत्र : रेशम क्षेत्र में केन्द्रीय रेशम बोर्ड केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण क्रियाकलापों के अंतर्गत 'सिल्क समग्र'-एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना में देशभर के स्टेक होल्डरों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। ये कार्यक्रम रेशम क्षेत्र में कौशल उत्पन्न करने और कौशल उन्नयन पर फोकस करता है ताकि नए प्रवेशकों के लिए रोजगार के अवसर (अधिकांशत: स्वरोजगार) सृजित किए जा सकें और उन्नत पैकेज अपनाकर मौजूदा उद्यमियों के आय के स्तर में भी वृद्धि की जा सके।

(ख): एकीकृत कौशल विकास योजना के अंतर्गत निधियां राज्य-वार जारी नहीं की जाती हैं। तथापि, पिछले 2 वर्ष के दौरान आईएसडीएस के अंतर्गत विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को जारी की गई निधि का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। हथकरघा क्षेत्र के एनएचडीपी/सीएचसीडीएस के अंतर्गत पिछले 2 वर्ष के दौरान झारखण्ड और अन्य राज्यों में कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के लिए डब्ल्यूएससी को जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। हस्तशिल्प क्षेत्र की एचआरडी योजना के अंतर्गत पिछले 2 वर्ष के दौरान झारखण्ड और अन्य राज्यों में कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए शिक्षण संस्थाओं/एनजीओ को कोई निधि जारी नहीं कर रहा है।

अनुबंध- I

झारखंड सहित सभी राज्यों में वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान एनजीओ , शैक्षिक संस्थानों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई निधि

(लाख रु. में)

क्र. सं.	संगठनों के नाम	2017-18 में जारी की गई निधि	2018-19 में जारी की गई निधि	कुल जारी
1.	आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड	60.61	0	60.61
2.	अंबिका शिक्षा समाज कल्याण समिति	124.50	20.75	145.25
3.	आंध्र प्रदेश डायरेक्टर हैंडलूम एंड टैक्सटाइल्स एंड अपैरल एक्सपोर्ट पार्क	122.92	0	122.92
4.	अपैरल रिटेल ट्रेनिंग एण्ड जॉब सौल्यूशन्स (एआरटीजेएस)	438.48	0	438.48
5.	अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन केंद्र (एटीडीसी)	799.00	0	799.00
6.	अरविंद लिमिटेड	69.75	0	69.75
7.	एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेनर्स ऑफ इण्डिया (एएलईएपी)	256.34	0	256.34
8.	बी के प्रिसिशन (इण्डिया) प्रा. लिमिटेड	68.58	0	68.58
9.	बेस्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	20.93	0	20.93
10.	भारत माता वेलफेअर फाउंडेशन	47.92	0	47.92
11.	भारतीय महिला ग्रामोद्योग संस्थान	56.00	4.34	60.34
12.	भास्कर फाउंडेशन	54.00	38.95	92.95
13.	बिरला कोट्सिन (इंडिया) लिमिटेड	489.91	100.46	590.37
14.	बीवीजी एजुकेशनल ट्रस्ट	76.87	18.25	95.12
15.	सैंटर फॉर एण्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (सीईडी), इण्डस्ट्रीज कमिश्नरेट, गुजरात सरकार	625.1	0	625.10
16.	सैंटम लर्निंग लिमिटेड	111.00	14.27	125.27
17.	सिबि इंटरनेशनल प्रा. लि.	98.02	0	98.02
18.	सीटीए अपैरल प्रा. लि.	55.86	0	55.86
19.	दक्ष फाउंडेशन	65.32	6.96	72.28
20.	डीवीआर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	90.56	15.14	105.70
21.	उद्योग और वाणिज्य विभाग, त्रिपुरा सरकार	0	6.82	6.82
22.	फेयर ट्रेड फ़ोरम - भारत (एफटीएफ-I)	47.27	0	47.27
23.	फ्यूजन ई सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	180.42	23.62	204.04
24.	ज्ञानोदय इंफोर्मेशन एंड एजुकेशन सोसायटी	52.55	0	52.55
25.	इण्डस इंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	57.42	0	57.42
26.	आईएल एंड एफएस क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिमिटेड	1333.38	0	1333.38

27.	इब्राहिम इंटरनेशनल लिमिटेड	191.85	0	191.85
28.	जान्हवी जेआईटीएम स्किल्स	160.38	27.99	188.37
29.	कर्नाटक स्टेट टेक्सटाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएसटीआईडीसीएल)	217.84	0	217.84
30.	खातोर फाइबर एंड फैब्रिक्स लिमिटेड	16.06	153.98	170.04
31.	मध्य प्रदेश लघु उद्योग (एमपीएलयूएन)	41.81	0	41.81
32.	महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च (एमएईईआर)	0	129.53	129.53
33.	मैट्रिक्स क्लोदिंग प्रा. लिमिटेड	557.92	0	557.92
34.	मॉडलमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	29.27	97.95	127.22
35.	मॉडर्न एजुकेशन सोसायटी	59.91	16.17	76.08
36.	मोनाश इंटरनेशनल लिमिटेड	171.60	4.60	176.20
37.	नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड	37.50	0	37.50
38.	निफ्ट - टीईए निटवेअर फैशन इंस्टीट्यूट	423.03	17.10	440.13
39.	उद्योग आयुक्त का कार्यालय, राजस्थान सरकार	146.90	0	146.90
40.	पीएमजी कॉमर्स एज फाउंडेशन	52.26	0	52.26
41.	पावरलूम डैवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल (पीडीईएक्सीआईएल)	22.44	1.15	23.59
42.	क्वेस कॉर्प लि।	0	24.10	24.10
43.	संवित एजुकेशन ट्रस्ट	148.81	33.62	182.43
44.	शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	41.81	0	41.81
45.	शिक्षा प्रसारिनी समिति	67.00	0	67.00
46.	श्री अमृतेश्वर ग्रामिनाभिवृद्धि शिक्षण और कल्याण समस्थे	85.82	0	85.82
47.	श्री टेक्नोलॉजीज	38.69	23.31	62.00
48.	श्री लक्ष्मी कोट्सिन लिमिटेड	8.73	0	8.73
49.	तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन (टीएएसएमए)	85.47	0	85.47
50.	टेक्नोपैक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	170.99	0	170.99
51.	दि क्लोदिंग मैनुफैक्चर्स एसोसिएसन ऑफ इण्डिया (सीएमएआई)	143.50	52.38	195.88
52.	अर्बो रूरल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एसोसिएशन (यूआरआईडीए)	61.17	23.94	85.11
53.	उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रिअल को-ऑपरेटिव एसोसिएशन (यूपीआईसीए)	120.22	44.39	164.61
54.	वजीर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	471.99	0	471.99
55.	वेलस्पन इंडिया लि	277.71	0	277.71
56.	विमेन एण्टरप्रेन्योर्स कर्नाटक एसोसिएशन (डब्ल्यूईकेएएस)	241.41	78.74	320.15

अनुबंध- II

पिछले दो वर्षों के दौरान एनएचडीपी / सीएचसीडीएस के अंतर्गत झारखंड और अन्य राज्यों में कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के लिए डब्ल्यूएससी को जारी निधियों का राज्यवार विवरण

(हथकरघा क्षेत्र)

क्र. सं.	राज्यों का नाम	2017-18		2018-19	
		शामिल बुनकरों की संख्या	जारी की गयी निधि (लाख रु. में)	शामिल बुनकरों की संख्या	जारी की गयी निधि (लाख रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	420	77.57	540	78.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	480	66.60		
3.	असम	6120	765.15		
4.	बिहार	280	41.86		
5.	छत्तीसगढ़	240	33.30		
6.	गुजरात	0	0.00		
7.	हिमाचल प्रदेश	320	49.62		
8.	हरियाणा			20	4.28
9.	जम्मू और कश्मीर	400	55.50		
10.	झारखंड	0	0.00		
11.	कर्नाटक	60	9.83	480	63.84
12.	केरल	160	22.20	220	28.74
13.	मध्य प्रदेश	0	0.00		
14.	महाराष्ट्र	0	0.00		
15.	मणिपुर	0	0.00		
16.	मेघालय	0	0.00		
17.	मिजोरम	700	47.46		
18.	नगालैंड	0	0.00		
19.	पंजाब			20	4.28
20.	ओडिशा	0	0.00	480	58.07
21.	राजस्थान	0	0.00		
22.	सिक्किम	0	0.00		
23.	तमिलनाडु	240	48.35	1000	153.6
24.	तेलंगाना	0	0.00		
25.	त्रिपुरा	0	0.00		
26.	उत्तर प्रदेश	420	17.12	100	13.02
27.	उत्तराखंड	120	13.64		
28.	पश्चिम बंगाल	0	0.00	280	53.59
	कुल	**9960**	**1248.20**	**3140**	**457.60**

अनुबंध- III

एचआरडी योजना के तहत 2017-18 से 2018-19 के दौरान झारखंड और अन्य राज्यों में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्वीकृत राशि की सूची (हस्तशिल्प क्षेत्र)

		2017-18		2018-19	
क्र. सं.	राज्य का नाम	आयोजित कौशल प्रशिक्षण की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)	आयोजित कौशल प्रशिक्षण की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)
1.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	असम	5	35.76	0	0
5.	बिहार	1	9.76	0	0
6.	छतीसगढ़	0	0	0	0
7.	चंडीगढ़	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0
10.	दिल्ली	1	9.98	0	0
11.	गोवा	0	0	0	0
12.	गुजरात	4	39.94	0	0
13.	हरियाणा	0	0	6	60.66
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
16.	झारखंड	0	0	0	0
17.	कर्नाटक	0	0	0	0
18.	केरल	0	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	1	7.8	0	0
20.	महाराष्ट्र	3	29.95	0	0
21.	मेघालय	2	20.22	0	0
22.	मणिपुर	0	0	0	0
23.	मिजोरम	0	0	0	0
24.	नगालैंड	0	0	0	0
25.	ओडिशा	1	31.85	0	0
26.	पांडिचेरी	0	0	0	0
27.	पंजाब	0	0	0	0
28.	राजस्थान	0	0	9	90.99
29.	सिक्किम	7	70.78	0	0
30.	तमिलनाडु	0	0	0	0
31.	तेलंगाना	0	0	0	0
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	15	109.81	12	121.36
34.	उत्तराखंड	0	0	0	0